INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

स्वच्छता की सामाजिकी और मुक्ति का सवाल

डॉ. सुमित उज्जैनवाल
राजनीतिक विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय

इस आलेख को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग के अंतर्गत उपनिवेशिक तथा उत्तर– उपनिवेशिक राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्वच्छता के प्रबंध के संदर्भ में दिये जाने वाले तकनीकी ज्ञान (Technological Knowledge) या उससे जुड़े विवादित मुद्दो को रेखांकित किया है। जो विशेषकर स्वयं में मैला ढोने की प्रथा एवं सफाई कामगार समुदाय की दयानीय स्थिति और राज्य के उस तकनीकी जाल का खुलासा करते हैं जिसमें सफाई कामगार (वाल्मीकि समुदाय) उलझता हुआ नजर आता है। इससे जुड़े तमाम पहलुओं को मैंने स्वच्छता की राजनीति जैसे रूपक के अंतर्गत रेखाकिंत किया है।

आलेख के द्वितीय भाग में मैंने मुक्ति के प्रश्न पर विशेष बल दिया है, जिससे जुड़े वाद–विवाद को सफाई कामगार समुदाय के पोषणकारी विकास (Sustainable Development) तथा सामाजिक नीति की आवश्यकता में महसूस किया है।

स्वच्छता की राजनीति से अभिप्राय

स्वच्छता एवं साफ सफाई के क्षेत्र में औपनिवेशिक तथा उत्तर औपनिवेशिक या अलग–अलग एजेन्सियाँ चाहे वे राष्ट्रीय हो या अन्तराष्ट्रीय काम करती रही है। हाँलाकि उनका उद्देश्य सफाई कार्मियों को मुक्ति दिलाना नही, बल्कि सफाई की बेहतर व्यवस्था करना रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमे औपनिवेशिक संरचनात्मक समझौते के राजनीतिक पहलूओ में नजर आता है। इसके दौरान राज्य स्वच्छता के नाश पर जिन प्रयोगात्मक तकनीक ज्ञान के चलते प्रबंध करता रहा उनमें साफ सुथरी व्यवस्था सिर्फ अभिजन वर्ग तक ही सीमित रही। वही समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़ा सफाई कामगार मजदूर गंदी तंग बस्तियों और मैला ढोने की प्रथा में फंसा रहा।

डी. एल. सेठ लिखते है– "उपनिवेशवादी राज्य ने दो भूमिकाएँ अख्तियार की। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की भूमिका में उसने पारंपरिक श्रेणीक्रम में जातियों की विवादित स्थितियों को स्थापित और पुर्नस्थापित किया। दूसरे, एक न्यायपूर्ण और आधुनिक शासक के रूप में उसने अपनी कमजोर और गरीब जनता के अधिकारों और आकांक्षाओं को चिह्नित करना चाहा अपने राजनीतिक अर्थतंत्र को उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के खतरो से बचाने में इन दोनों भूमिकाओं ने राज्य

की मदद की। उनका मानना है कि उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था की कुछ ऐसी खास नीतियाँ भी थी जिनका लक्ष्य पारम्परिक सामाजिक अभिजात्यों की सत्ता को अपने शासन के लिए समर्थन पैदा करना था।[1]

जैसाकि अपने आलेख के प्रथम पाठ में मैंने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि जब उपनिवेशिक सरकार भारत में आई तब एक अभिजन तबके ने स्वच्छता के पर्यावरण में जीवन जीने के अधिकार की मांग प्रारम्भ की। हॉलाकि स्वच्छता के पीछे ब्रिटिश सरकार की भी अपने हित में छिपी मंशा इस रूप में थी कि एशिया में हेजे जैसी महामारी से कैसे निपटते हुए अपने को सुरक्षित किया जाए। परन्तु इस बीच ब्रिटिश सरकार की स्वच्छता की राजनीति को उर्दू के अखबारों में निरंतर असमान स्वच्छता साफ सफाई के असमान प्रबंधों के संदर्भ में विद्रोह के रूप में रेखांकित किया गया। अतः ब्रिटिश सरकार द्वारा शहरी दिल्ली को सुरक्षित रखने की मुहिम को असमानता पर आधारित माना गया।[2] अतः आधुनिक शासक के रूप ब्रिटिश सरकार कमजोर और गरीब सफाई कामगारों के अधिकारो के अधिकारों और आकांक्षाओं को चिह्नित नहीं कर पाई ।

एक अहम प्रश्न मानो इस पूरी वर्ता में दम भर देता हैं जो इस रूप में है कि शहर को सफाई कामगारों से मुक्त करने जैसे प्रश्न के सम्बन्ध में टेक्नोलॉजी का या तकनीकी ज्ञान का अपना स्थान कहाँ है ? वास्तव में यह एक ऐसा प्रश्न है जो बार–बार ऊपरी संरचना पर प्रश्न चिह्न तथा ज़मीनी स्तर से विद्रोह के रूप में सच्चाई का बयान करता है।

उपनिवेशिक सरकार घोषित करती है कि जहाँ एक तरफ सफाई कामगार समुदाय तबका विकास के मुद्दे को अतीत से अपनी संकल्पना में रखे हुआ है। वही दूसरी तरफ तकनीकी ज्ञान (Technological Knowledge) जिससे आशा की जाती रही कि वह व्यवहार में सफाई कामगारो द्वारा हाथो से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करेगी। इसके बावजूद तकनीकी ज्ञान की उपस्थिति सफाई कामगारों की भूमिका को कम करने में नकाम रही। इसके उपरान्त सफाई कामगार पूछते नजर आते है कि आखिर क्यों तकनीकी ज्ञान (Technological Knowledge) हमारी मुक्ति दिलवाने में असफल रहा? आज दिल्ली में सफाई कामगार (Manual Sweepers) मानक है वही मेक्नाईज टेक्नोलॉजी एक अपवाद बन कर रह गई है। जैसाकि विजय प्रसाद का मानना है कि आज

---

1 D.L. Seth (1999), Secularization of Caste and Making New Middle Class, Economicand Political Weekly, Aug. 21-28.

2 David Arnold (1993), Colonizing the Body State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth Century Indian, Berkeley: University of California press

सफाई कामगार समुदाय हाथों से मैला साफ करने जैसे अमानवीय कार्य से लेकर जटिल तकनीकी ज्ञान में नजर आता है।[3]

पूर्व–आधुनिक शहर कूड़ा–करकट साफ करने हेतु सफाई कामगार द्वारा प्रयोग में लाने वाले ठेला गाड़ियों तथा झाड़ू द्वारा सफाई करने वाले तौर–तरीको पर आधारित थी। परन्तु अग्रेजी सरकार के आगमन के उपरान्त 1832 में तेजी से एशिया में फैली हैजे जैसी महामारी पर नियंत्रण पाने तथा गंदे पर्यावरण की समस्या से तुरन्त बुर्जवा वर्ग को इस पर निम्न सहिष्णुता के लिए प्रेरित किया । 19 वीं शताब्दी के मध्य काल में म्यूनिसिपल कारपोरेशन बदलाव के लिए सामने आती नजर आई।

अब माना जाने लगा कि सिर्फ गली गुच्चों की सफाई ही काफी नहीं। अब तकनीकी ज्ञान (Technical Knowledge) ने इस समय की तमाम समस्याओं को बताने की कोशिश जारी करी। शहर के निर्धारित क्षेत्र सीमा में मल – व्ययन (Disposalof Night soil) की समस्या को कम समय में सड़ाने या गलाने (Decompose) की व्यवस्था आरम्भ की गई। जैसाकि 1914 में औपनिवेशिक अधिकारी ने लिखा था मैला साफ करने की कुशलता या सकक्षम प्रणाली के विचार का अभिप्राय पूर्ण रूप से मल–व्ययन को शहर के आस–पास एवं रहने के स्थान से हटाने तथा इसके सड़ाने या गलाने की प्रक्रिया ऐसी हो जिसको बढ़ चढ़कर देखा जा सके।[4]

जब औपनिवेशिक सरकार का रूख सिर्फ बेहत्तर सफाई की व्यवस्था करने तक ही सीमित हो जाए, तब ऐसे में सफाई कामगार समुदाय को मल–व्ययन के काम में शहरीकरण और आधुनिकीकरण की बतौर प्रक्रिया में मुक्ति नहीं है। वही अब दूसरी ओर सेनिट्री इंजीनियरों, (Sanitary Engineers) ने अब मल–व्ययन तथा कूड़ा–करकट को हटाने के प्रश्न को एक नव वैज्ञानिक तरीके पर आधारित लक्ष्य के साथ रेखांकित किया, जिन्होंने अब एक नव– तकनीक सिवर सिस्टम को प्रस्तुत किया । जिसकी प्रक्रिया पिछले प्रबंधों से ज्यादा उच्च स्तर की मानी गई। परन्तु इस तकनीकी ज्ञान का खुलासा 1870 में हुआ। 1870 में उर्दू के अखबारों में तथा स्थानीय समाचार पत्रो में रिकॉर्ड किया गया जिसमें स्वयं में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिखर सिस्टम (Sewage question) में असफल होती नजर आई। इसके तहत खुलासा किया गया कि जो सिवर म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने निर्मित किये थे। उनका हाल बेहाल सा है बारिश के मौसम में सिवर ब्लॉक होने के कारण अधिकांश मोहल्लों में गन्दा पानी एकत्रित हो जाता है जिसके पास से गुजरना मानो बड़ी समस्या है।

---

3 Vijay, Prashad (2000), Untouchable Freedom: A Social History of Dalit Community New Delhi: Oxford University Press

4 Delhi State Archives (1884), Chief Commissioner (Education), B Progs. No 183.

स्वच्छता के बदलावों के प्रारंभिक दिनों में इतिहास में इंजीनियरों तथा प्रशासकों ने महसूस किया कि वास्तव में आधुनिक टेक्नोलॉजी अस्वच्छता की समस्या से लड़ने में नाकाम रही है। गौरतलब है कि सेनिटी इंजीनियरों तथा प्रशासकों ने इस असफलता का दोष सीधे–सीधे वैज्ञानिक तथा आधुनिक तकनीकी ज्ञान की असफलता की बजाय वित्तीय सहायता की कमी तथा सामाजिक रूप से स्वच्छता के नियमों को स्वीकार न करने में असफलता को सूचीबद्ध किया।[5]

इस लिहाज से आनन्द तेलतुम्बडे का कहना सही है कि 'इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता भारत के सामाजिक मामलो में ब्रिटिश उपनिवेशवादी राज्य के कृपापूर्ण हस्तक्षेप के पीछे उसकी जटिल रणनीति ही काम कर रही थी।[6]

यदि आज के संदर्भ में इसकी प्रांसगिकता की जाँच की जाए तो स्वच्छता के नाम पर राज्य के चरित्र की विशेषता पर औपनिवेशिक छाप सी लगी नजर आती है। इसका खुलासा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सक्रियावादी मुकेश सूद ने विशेषकर पब्लिक वर्क विभाग के संदर्भ में 23 सितम्बर में 2013 किया।

उन्होंने समाचार पत्र में बताया कि हाँलाकि मानसून समाप्त हो चुका है परन्तु आज भी दिल्ली के राजोरी गार्डन इलाके में सिवरों की डि– सिलटिंग का कार्य ज्यो का त्यो पड़ा है। इसके बवाजूद भी गंभीर समस्या पर राजनीति होती नजर आती है क्योंकि संघ प्रशासन एक–दूसरे पर आरोप लगाता नज़र आ रहा है। पब्लिक वर्क विभाग के अधिकारी का कहना है कि यहाँ कार्य साऊथ कारपोरेशन के द्वारा किया। गया था। लेकिन जब एक साल पहले यहाँ विकास की आड़ में सिवर लाईने डालने का काम पब्लिक वर्क विभाग पूर्ण कर चुका है तब आज भी सिवर क्यों खुले है?[7] हाँलाकि भारतवर्ष में 2013 का मैला प्रथा कानून निर्मित किया गया है जिसमें सोशल जस्टिस मंत्रालय में इसके लागू करने के प्रावधानों पर सिवर सिस्टम को भी कानूनी सीमा के दायरे में लिया गया है। परन्तु जब स्वच्छता और विकास की आड़ में इन सिवरों की सफाई जो ऊपर तक मानव मल से भरे हो रात में करवाई जाए तब क्या यह मैला ढोने वालों की मुक्ति का विकल्प होगा? नीरजा गोपाल जायल का कथन सत्य ही है कि "स्वतंत्रता की संध्या पर विकास की लम्बी चौड़ी अवधारणा स्वयं में सम्पूर्णता के विचार में शामिल थी।

---

5 Vijay, Prashad, (2001), The Technology of Sanitation in Colonial Delhi, Modern Asian Studies, Vol. 35, pp. 113-155, Cambridge University Press.

6 आनन्द तेलतुम्बडे, (2008), 'दलितों में साम्राज्यवाद विरोधी चेतना' (सम्पादक), तेज सिंह, अम्बेडकरवादी विचारधारा और समाज, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली ।

7 Risha, Chillingly (2013), Blame Game by PwD Corporation Over Desilting, Times of Indian 23 Sept.

परन्तु वहीं दूसरी तरफ भारतीय राज्य के आधुनिकीकृत गैर–वार्तालापीय (Non-Negotiable) एजेण्डे का भी भाग थी।[8] जो आज प्रांसगिक समय में इसी विचार में जीवित है।

अतः कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक राज्य ने भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण सिर्फ अपने शासन के हित में किया, जिसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे है। इससे भारतीय समाज का मौलिक रूपान्तरण ने होकर केवल कार्यात्मक (Functional) रूपांतरण हुआ, जो कि अंग्रेजो के हित में भारतीय समाज का मौलिक रूपान्तरण तब तक सम्भव नहीं जब तक समाज में निचले पायदान पर खड़े वाल्मीकि समाज (सफाई कामगार समुदाय) का पोषण कारी विकास नहीं होता। अतः कहने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि शताब्दियों में हमारा आगमन स्वतंत्र समाज और राज्य के रूप में नहीं वरन् औपनिवेशिक राज्य की अधीनस्थ शाखा के रूप में हुआ।

सम्भवतः भारत और उके समीपवर्ती देशों में शौचालय निर्माण का कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में पहला संगठित 1930 में किया गया। इसके तहत राक फेलर काउण्डेशन द्वारा पहले श्रीलंका में और फिर भारत में स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की गयी। बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई (जो उस समय एक प्रान्त था) और मद्रास (जो उस समय एक प्रेसीडेन्सी थी) में स्थापित इन स्वास्थ्य केन्द्रों में बंध छिद्र गड्ढा (बोर होल) शौचालयों को आजमाया गया।

इन शौचालयों में बैठने के लिए पहले ढाले गये स्लैबो का प्रयोग किया जाता था। इन प्रयासों को यद्यापि कुछ सफलता मिली लेकिन इनमें कुछ कठिनाईयाँ थी। इन्हे घरो के भीतर बैठाना और बंध छिद्र गड्ढो के भर जाने के बाद शौचालयों को दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था। अर्थात् उन्हे साफ करना बेहद ही अमानवीय कार्य था। इस तरह के शौचालयों में वाटर सील की व्यवस्था न होने के कारण दुर्गन्ध और मक्खियों के प्रजनन की समस्या थी ।

प्रारम्भिक अनुभवो के बाद बंगाल के सिंगूर स्वास्थ्य केन्द्र पर गड्ढे के ठीक ऊपर वाटर सील पैन लगाने का विचार विकसित हुआ। यह निश्यित रूप से एक सुधार था लेकिन इसके डिजाइन के बारे में मुख्य शिकायत यह थी कि इसके इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति पर पानी के छिंटे पड़ते है। इस तरह की मानसिकता स्वयं में दर्शाती है कि शताब्दीयों में हमारा आगमन स्वतंत्र समाज और राज्य के रूप में नहीं औपनिवेशिक राज्य की अधीनस्थ शाखा के रूप में हुआ। जहाँ पर एक तरफ अभिजन्न (उच्च जाति) के लोग है जिनकी इस प्रकार के डिजाइनों वाले शौचालयों के बारे शिकायत है कि इसके इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति पर पानी के छिंटे पड़ते हैं। परन्तु इन अभिजन्न वर्ग को मैला साफ करने वाली मानवजाति की तानिक भी चिंता नहीं जो इस अमानवीय कार्य में फंसी है।

[8] Niraja, Gopal Jayal (1991), Democracy and the State, OÛford University Press] NewDelhi.

यहाँ पर रणजीत गुहा के तर्क को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। रणजीत गुहा ने औपनिवेशिक राज्य को वर्चस्वहीन प्रमुख (Without Hegemony) के रूप में रेखांकित किया है। गुहा का कहना है कि उपनिवेशवाद के दमन की संरचना गैर–वर्चस्ववादी थी, जिसमें बल का प्रयोग भारी पड़ता था। दरअसल, यह जरूरी नहीं है कि सत्ता के खेल में संघर्ष की वास्तविक स्थितियों में दमन करने और बल का प्रयोग करने के बीच हमेशा स्पष्ट अन्तर करना सम्भव हो । सत्ता के तमाम सामाजिक सम्बन्ध बलवत् कायल करने या कायल करके दमन करने का हो सकता है। वर्चस्व इस तरह राज्य और समाज के बीच सत्ता सम्बन्धों का पूर्व निर्धारित क्षण नहीं होता बल्कि उसकी रचना सफल असफल वर्चस्वधर्मी परियोजनाओं की श्रृंखला के दौरान होती है।[9] स्वच्छता के नाम पर या मैला प्रथा से मुक्ति के नाम पर प्रयुक्त कह जाने वाले ज्ञान से जब जमीनी स्तर की समस्याओं का पूर्ण निधान ही नहीं हो पाता। तब ऐसे आधुनिक तकनीकी ज्ञान को यहाँ गुहा के तर्क में वर्चस्वधर्मी परियोजनाओं की श्रृंखला माना जाना गलत नहीं होगा ।

इसके अलावा यह सत्य है कि गाँधी जी के जीवन काल में सफाईकर्मियों को मुक्त कराने के बहुत से प्रयास किये गये परन्तु उनका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, यह कि भारत पर उस समय विदेशी शासन था और सरकार ने सफाईकर्मियों की मुक्ति के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किया, और दूसरा, यह है कि उस समय सीवर तथा सेप्टिक टंकी प्रणालियों की जगह कोई दूसरी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी। परन्तु संयोगवश, 1969 में गाँधी शताब्दी के दौरान सफाईकर्मियों को सिर पर मैला ढोने की बुराई से मुक्ति दिलाने के आन्दोलन का प्रारम्भ डॉ. विन्देश्वर पाठक ने प्रारम्भ किया। जो स्वयं में मानो गांधी जी के अधूरा कार्य को पूरा करने की दिशा में कदम था। जिन्होंने स्वच्छता के लिए टू पीट अर्थात् दो गड्ढों वाली तकनीक का प्रयोग किया। दोनों गड्ढों का इस्तेमाल बारी–बारी से होता है। एक गड्ढे के भर जाने पर मल भूत को दूसरे गड्ढे में छोड़ा जाता है।[10]

वास्तव में सुलभ शौचालयों में कायम दो गड्ढ़ों (Twopitsystam) वाली व्यवस्था संस्कृतिक, आर्थिक रूप से स्वीकार करने वाली है। इतना ही नहीं बल्कि स्वयं में यह मैला ढोने वाली व्यवस्था के लिए स्वच्छता को मध्य नजर रखते हुए एक विकल्प है। इस तरह वाल्मीकि समुदाय (सफाई कामगारों) की मुक्ति हेतु 1970 से एक संगठन निर्मित किया गया जो सुलभ इंटरनेशनल के नाम से जाना गया।

विन्देश्वर पाठक ने साफ तौर से अहसास किया कि शताब्दीयों से शोषित तथा संस्थानों द्वारा प्रताड़ित वाल्मीकि समुदाय की मुक्ति का संकल्प इतना आसान नहीं है। इस विचार को

---

9 Ranjeet, Guha (1998), Colonialism in South Asia : Hegemony Without Hegemony and Its Histrography, Oxford University Press, Delhi.

10 S. Tripathy (2004), "Sulabh international : A Conscious Effort in liberating and Rehabilitating Scavengers", in Gopal Singh (eds) Restoration of Human Right and Dignity to Dalits, Manak Publication, New Delhi.

मध्य नजर रखते हुए उन्होंने वाल्मीकि समुदाय के पोषण कारी विकास हेतु उन्हे दूसरे नए व्यवसायों में शमिल करने हेतु ट्रेनिंग्स तथा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने हेतु दिल्ली में स्कूल खोले जो पाठक जी के संयोजन में कार्यरत है।

जैसाकि भारतीय शासन की राजनीति का इतिहास इस बात का गवाह है कि 1970 के दशक के उत्तरकाल और 1980 के दशक में 'राज्य' नियंत्रित विकास को दक्षिण और वाम दोनों पक्षो से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पंथियों ने बाजारी अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप को अर्थव्यवस्था की अक्षमता का कारण माना जिसकी वजह राजनीतिज्ञों और नौकरशाही का 'किराया वसूली' का व्यवहार होता है। वामपंथियी का आरोप था कि विकास का लाभ राजनेताओं नौकरशाही के गठबंधन ने उठाया है। इस संदर्भ में गौरतलब है कि 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने भी स्वीकार किया था कि विकास के लिए निर्धारित राशि का 15 प्रतिशत भी आम जनता तक नहीं पहुँच पाता।[11] चूंकि स्वच्छता का एक संकल्प राजीव गांधी के प्रधानमंत्रीत्व काल में भी लिया गया और सुलभ में शुष्क शौचालयों में शौचालयों को इस कसौटी पर खरा उतरते देखने हेतु 1980–81

राहत पाने हेतु जल चलित शौचालयों हेतु केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय निकायों (MCD) को वित्तीय सहायता प्रदान करी । परन्तु परिणाम उतने संतोष जनक नहीं मिले जितने की आशा कि गई थी। एम. एन. श्रीवास्तव का कहना है कि इस योजना का अपने प्रारम्भिक स्तर पर मंद रूप से दिखाई देने का सबसे बड़ा कारण सालभर में सिर्फ दो तीन शहरो का चयन करके उन पर काम करना था। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण कारण स्थानीय निकायों को केन्द्रीय सरकार की तरफ से दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कमी का होना था।[12]

अतः यहाँ पर रूडोल्फ और रूडोल्फ (1987) के तर्क को समझने की जरूरत है जो राज्य के चरित्र को समझने में मदद करेगा। रूडोल्फ और रूडोल्फ ने स्वतंत्र में राष्ट्र–राज्य को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हुए कहा है, "आधुनिक भारत के संविधान के संस्थापकों को 'राज्यपन' की उस विरासत का लाभ मिल गया जिसे हिन्दू, मुगल और विरासत का लाभ मिल गया जिसे हिन्दू, मुगल और ब्रिटिश उपमहाद्वीपीय साम्राज्यों ने छोड़ा था। उन्होंने केन्द्रीय कृत शासन के साथ–साथ क्षेत्रीय राज्यों को समांतर राज्य सरंचना का संगठित रूप प्रस्तुत किया।"

---

[11] शिव नारायण सिंह अनिवेद (2005), 'आधुनिक भारत की द्वंद्व – कथा (प्रभुत्व और प्रतिरोध का द्वंद्वात्मक विमर्श), वाणी प्रकाशन, दिल्ली

[12] B.N. Srivastava, (1997) 'Manual Scavenging in India A Digrace to the country, Concept Publishing Company, New Delhi-

क्योंकि राज्य का नियंत्रण अभिजात शासक वर्ग के हाथ में था। विडंबना यह थी कि उन्होंने उपनिवेशवाद से प्राप्त स्वतंत्रता के विरासत की वैधता को राज्य के उसी बुर्जआ ढाँचे और व्यवस्था को सौंप दिया, जिसका निर्माण औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ था।

राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास की वर्चस्वधर्मी परियोजनाएँ, औपनिवेशिक बुर्जआ प्रशासनिकदृसैनिक व्यवस्था जारी रखने का तार्किक आधार बनी। गुलामी की स्थिति में जब देश का भू–भाग, जीविका – अर्थव्यवस्था के साधन ही दूसरे कब्जे में हो, तो शसित समाज में राष्ट्र की भावना आसानी से जागती है। सामाजिक मतभेद (वर्ण–जाति–वर्ग का) जो स्वतंत्रता के बाद अब फूट–फूट कर उभर रहे है, ये सभी औपनिवेशिक काल में गौण थे।[13] अतः कहा जास कता है कि 1970–1980 के भीतर राज्य ने स्वच्छता के नाम पर जो पूंजी एकत्रित करी उसका लाभ चंद बुर्जुआ वर्ग (उच्च जाति) के लोगों को हुआ न ही मैला – प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो पाई और मैला प्रथा का मुद्दा सफाई कामगारों की नजर में अभी तक ज्यों का त्यों बरकरार रहा। इसके अलावा स्वच्छता की मुहिम में कार्यरत सफाई कामगारों को उनकी बस्तियों में 'स्वच्छता' का रत्तीभर भी लाभ होता नजर नहीं आया।

शिक्षा विकास की कुंजी

शिक्षा ही विकास और बदलाव की कुंजी है। भारत वर्ष में शिक्षा का स्तर अव्वल तो निचला है विशेष तौर से वाल्मीकि समुदाय में जो स्वयं पिछड़ो में अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं प्रासंगिक समय में शिक्षा का स्तर दर बदर बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा गरीब परिवार के बच्चों के विकास हेतु योजनाएं निरंतर जारी है परन्तु वाल्मीकि समुदाय के बच्चों के विकास हेतु सरकारी शिक्षा तथा नौकरीयों में आरक्षण अलग से दिया जाने की जरूरत है।

आरक्षण की जो व्यवस्था की गई उसमें अनुसूचित जातियों की राज्य स्तरीय सूचियाँ बनाई गई और सभी मलिन पेशा जातियों को मिलाकर एक नाम अनुसूचित जाति देकर आरक्षण दे दिया गया । यही से एक नई समस्या का उदय हुआ। इस पर उसी दिन से एतराज दर्ज करवाने की कोशिश जारी है। उभर सिंह स्वोकंट नाम के एक विधायक ने जवाहर लाल नेहरू को पत्र भेजा जिसके जवाब में सहमत होते हुए तत्कालीन ने कहा आपका कहना कि दलितों में रविदासी (चमार) अन्य सबसे आगे है बहुत ठीक है। हमें अन्य दलितों को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए । यह वैसी ही स्थिति है जैसे किसी स्कूल में दिए जाने वाला खाना एक थाली में परोस दिया जाए। तब उन बच्चों में ताकतवर तथा चतुर बच्चे दूसरों के जाएँगे। ऐसी ही विकट परिस्थिति का सामना वाल्मीकि (सफाई कामगार) कर रहा है। सफाई के कार्य के

[13] शिव नारायण सिंह अनिवेद (2005), स्वराज : अत्तर – औपनिवेशिक समाज में स्वतंत्र राष्ट्र राज्य, आधुनिक भारत की द्वंद कथा (प्रभुत्व और प्रतिरोध का द्वंद्वात्मक विमर्श, वाणी प्रकाशन ।

अलावा वाल्मीकि समाज को कही भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। केवल नौकरीयों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी कमोवेश यही स्थिति है।[14]

दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वाल्मीकि समुदाय का प्रतिनिधित्व

Year	Total	SC	No. of Seats Contested by Valmikis	No. of Seats Seates won by valmikis
1958	80	12	2	2
1962	80	12	2	2
1967	100	13	2	1 (congress)
1972	100	13	2	1 (congress)
1977	100	15	4	2(congress)
1983	100	15	4	2(congress)

तालिका 1 में ऊपर दी गई सूचना में सन् 1983 के उन आँकड़ों पर गौर फरमाया गया है जिसमें वाल्मीकि (सफाई कामगारों) के चुनावी प्रतियोगिता में भागीदारी (विशेषकर नगर निगम के चुनावों) का विश्लेषण दिया गया है। 1958 में जहाँ कुल 80 सीटों में से कुल 12 सीटों को पूरे दलित समुदाय के लोगों के लिए, संरक्षित किया गया है परन्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि वाल्मीकि (सफाई कामगारों) को केवल 2 सीटों पर लड़ने का मौका मिला। जिनमें 2 सीटों पर प्रतियोगिता में वह विजयी भी होते नजर आते है। वहीं 1962 में कुल 80 सीटों में से 12 पूरे दलित समुदायों के लिए आरक्षित की गई जिनमें से केवल पहले ही की तरह 2 सीटों पर वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर विजयी भी हुए। वहीं 1967 और 1972 के चुनाव में कुल दलित समुदायों की सीटें संरक्षित सीटों में बढ़ोत्तरी हुई कुल 13 सीटें पूरे दलित समुदाय के लिए संरक्षित हुई । परन्तु दोनों ही कालों में सफाई कामगारों (वाल्मीकि समुदाय) का प्रतिनिधित्व बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। सिर्फ 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और विजयी भी हुए। सन् 1977 से 1983 तक के चुनावों में कुल 100 सीटों में से 15 सीटें जो बढ़ती हुई पूरे दलित समुदाय के लिए संरक्षित हुई परन्तु सफाई कामगारों (वाल्मीकि) को केवल दोनों ही वर्षों में दो–दो सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला और कांग्रेस से विजयी भी हुए।

[14] Source Delhi Gazetter, 1976, 735 1983 Figuers from Hindustan Times after Feb 1983, election 1977 figuers were

वाल्मीकि समुदाय के लोगों को हटाकर अनुसूचित जाति का केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व का ब्यौरा 1971 से 1991

द्वितीय तालिका

S.No	Category (श्रेणी)	(वर्ष) Year 1971	वर्ष 1991
1.	श्रेणी (Class)	2.58	0.09
2.	श्रेणी द्वितीय (Class III)	4.06	11.82
3.	तृतीय श्रेणी (Class II)	9.59	15.65
4.	चौथी श्रेणी (Class IV)	18.37	21.24

Source (स्रोत): Eighth Five Year Plan, 1992-97, Vol II.

वहीं तालिका 2 में प्रथम श्रेणी की नौकरियों पर यदि ध्यान दिया जाए तब ज्ञात होता है कि सफाई कामगारों का प्रतिनिधित्व अन्य दलित जातियों की तुलना पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालाँकि द्वितीय श्रेणी, तृतीय और चौथी श्रेणियों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। उदाहरण के लिए रेलवे में चौथी श्रेणी की नौकरियों में सफाई कामगारों को भारी मात्रा में मैला ढ़ोने के लिए पृथक और नौकरियों में शामिल किया जाता रहा है। आखिर राज्य की राजनीति किस तरह का कल्याणकारी योजनाओं का मुखौटा ओड़े हुए है।

अतः कहा जा सकता है कि मैला ढोने की प्रथा को हटाने हेतु राज्य की तरफ से अधिक से अधिक नीतिया कायम की जा रही है। इस दौरान मैला प्रथा को हटाने हेतु कानूनी फरेम वर्क भी निर्मित किया जा चुका है। परन्तु फिर भी मैला प्रथा जारी है। इस संदर्भ में सामान्यतः निरन्तर बहाने बाजी इस रूप में की जाती रही है कि भारत में चुकी खुले में शौच करना हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। इस करके प्रथा जारी हैं यदि सफाई कामगार समुदाय मैला साफ न करे तब स्वच्छता और साफ सफाई का हमारा संकल्प मात्र एक सपना ही बन जाएगा क्योंकि और अन्य समुदाय इस गंदे काम को करने के लिए तैयार नहीं होगा।

इस तरह का विरोधाभास हटाने हेतु आज सफाई कामगारों (वाल्मीकि समुदाय) के पोषणकारी विकास (Sustainable Denelopment) का होना आवश्यक मुद्दा है[15] जिसके दौरान तमाम

[15] डी.के. वर्मा के अनुसार पोषणकारी या सतत् विकास की आवधारणा से अभिप्राय भावी पीढ़ियों हेतु प्रकृतिक संसाधनो को सुरक्षित बनाये रखने वाली रणनीति से है । परन्तु इस अध्याय में पोषण कारी विकास का अभिप्राय विज्ञान तथा सामाजिक पहलुओं के संदर्भ में है। डी.के. वर्मा का मानना है कि आज मैला ढोने की प्रथा विशेष परिप्रेक्ष्य में पोषण कारी विकास को नये सिरे से समझने की आवश्यकता है, जिसका सीधे–सीधे सम्बन्ध सामाजिक पर्यावरण से है।

केन्द्रीय नीतियों एक भिन्न प्रकार की सामाजिक नीति की आवश्यकता है। जहाँ तक सवाल ट्रेनिंग्स का है तब कहा जा सकता है कि इस रूप में केवल आर्थिक मुद्दों पर ही बल न देकर सामाजिक गरिमा पर आधारित बल देना आवश्यक है जो सिर्फ और सिर्फ मानव–जाति की मानसिकता में बदलाव के द्वारा ही पूरी हो सकती है। पोषणकारी विकास के विचार में सामाजिक नीति की एक अन्य आवश्यकता बराबरी की हैसियत (भारत के नागरिक) होने के रूप में है। अर्थात् उन्हे भी राज्य को गरिमा पर आधारित व्यवसायों में तब्दील करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए बजाय किसी छूआ–छूत के व्यवहार की अपमार्जको (वाल्मीकि सफाईकामगार समुदाय) की मुक्ति एवं पुनर्वास अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक संवेदशील समूह वाल्मीकि एवं झाड़कशो का है। उनकी कार्य परिस्थितियाँ आज भी दयनीय है। मल की टोकरियों एवं बाल्टियों को सिर पर रखकर ले जाने की व्यवस्था आज भी बहुत से हिस्सो में अदृश्य रूप में प्रचलित है। यह व्यवस्था इन क्षेत्रों में अस्वच्छता के फैलने के लिए ही आरदायी नहीं है, वरन् इसके परिणामस्वरूप अस्पृश्यता की प्रथा को निरन्तरता भी प्राप्त होती है। अधिकांश सफाई कामगार कचरा फेंकने के स्थानों के निकट रहते हैं उनके लिए जहाँ आपासीय बस्तियां स्थापित भी की गई है वहाँ भी साफ सफाई की आवश्यक दशाएँ सीमित है।[16]

सूखे शौचालयों को जलचालित शौचालयों के रूप में परिवर्तित करने हेतु, पांचवी पंचवर्षीय प्रावधान के साथ केन्द्रीय कार्य एवं आवसीय मन्त्रालय ने एक केन्द्र प्रवर्तित योजना को प्रारम्भ किया। इस प्रकार के हस्तक्षेपो के बवाजूद सफाई कामगार (वाल्मीकि समुदाय) की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया।

अतः छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र प्रवर्तित, सफाई कामगारों (वाल्मीकि समुदाय) की मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय योजना को 1981 में लागू किया गया जो 50:50 प्रतिशत सुमेलित अनुदान पर आधारित है, तथा जिसका उद्देश्य चयनित लघु एवं मध्यम आकर के नगरों में सम्पूर्ण नगर अभिगम के आधार पर वर्तमान में भी पारिवारिक एवं सामुदायिक शुष्क – शौचालयों को जलवादिहत शौचालयों के रूप में परिवर्तित करना एवं बेरोजगार सफाई कामगारों वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वासित करना है। उनके पुनर्वास की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में उनके नाना रूपकरण हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण को भी एक घटक के रूप में इस योजना में सम्मिलित किया गया है।

सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर विचार करने के लिए इस आवश्यकता पर भी बल दिया है कि राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का निर्माण किया जाए जिसमें नगर विकास विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि हो तथा अनुसूचित जाति विकास निगमों को चाहिए कि वे सफाई कामगारों से सम्बन्धित समस्या क्षेत्रों

[16] सुखदेव थोराट (2013), 'भारत में दलित सामान्य लक्ष्य की खोज, सेज पब्लिकेशन 2013, नई दिल्ली।

की खोजे और उपयुक्त हस्तक्षेप करे चूंकि सफाई कामगार समुदाय (वाल्मीकि समाज) में बच्चों की शादी जल्दी कर दी जाती है और न ही वे परिवार नियोजन पर बल देते हैं उनका मानना है कि ज्यादा बच्चों के होने पर कमाई में बढ़ोत्तरी होती है जो घर खर्च में अहम् रोल निभाते है। ऐसे में परिवार नियोजन आवश्यक है, जो सिर्फ नगर निगम स्वास्थ्य परिवार नियोजन के माध्यम से हो सकता है।

सरकार यह भी महसूस करती है कि सफाई कामगारों के विस्थापन एवं प्रशिक्षण के मध्य का समय अन्तराल उनके उद्धार की नीतियों के उद्देश्य को निष्फल कर देता है अतः इस दिशा में सम्मलित प्रयास किए जाने चाहिए।

यह बात सत्य है कि भारत में मैला ढोने वालों को प्रत्येक सरकार से आश्वासन निरंतर शब्दाडंबरों में मिलता रहा है। नई दिल्ली में 9 अक्टूबर 2013 में राहुल गाँधी द्वारा मैला ढोने वालों के प्रति चिंता जाहिर करने के एक दिन बाद केन्द्र सरकार 10 अक्टूबर बुधवार को उनके लिए कई घोषणाएँ की ।

वाल्मीकि जयंती के अवसर पर राहुल गांधी और शीला दीक्षित सफाई कामगार समुदाय को 1993 में बनाये गये कानून की कमियों और 2013 में लागू किये गये नये कानून के संदर्भ में आश्वासन देते हुए नजर आए।

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM